खण्ड–5, अंक–1, वर्ष–2017, मु0पृ0 36–46, D.O.I. : 10.22445/avsp.v5i01.9845 शोध पत्र

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की चुनौतियां व अवसर–नाबार्ड द्वारा उत्तराखण्ड में की गई पहल के विशेष सन्दर्भ में

प्रीति पन्त
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
preetipant@gmail.com

प्राप्त तिथि–29.06.2017, स्वीकृत तिथि–12.08.2017

सार– चीन के बाद विश्व के द्वितीय अग्रणीय खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र होने के पश्चात् भी भारत वैश्विक खाद्यान्न व्यापार में मात्र 1.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। यह विनियोजकों एवं निर्यातकों के लिए अभूतपूर्व अवसर दर्शाता है। इस परिपेक्ष्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि वे हमारी अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तम्भों– कृषि एवं उद्योगों में सक्रिय सम्बन्धों व सहयोगों को प्रोत्साहित करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के कुल खाद्य बाजार का 32 प्रतिशत है तथा उत्पादन, उपभोग, निर्यात व सम्भावित वृद्धि के अनुसार पाँचवां स्थान रखता है। निर्यात की अत्यधिक सम्भावनाएं रखने वाले खाद्य प्रसंस्कृरित उत्पाद भारत के कुल निर्यातों का 13 प्रतिशत है। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के ग्रामीण विकास, जो राष्ट्रीय विकास की धुरी है, में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसे देखते हुए "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक"(नाबार्ड) इन उद्योगो के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। यह पहल उत्तराखंड जैसे प्रदेश में और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें वर्ष 2013 में जल प्रलय से भीषण क्षति हुई है। यह शोध पत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के चालक एव अवरोधों का नाबार्ड द्वारा उत्तरखंड में की गयी पहल के सन्दर्भ में समीक्षात्मक एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करता है। इस क्षेत्र द्वारा भविष्य में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देने के लिए इन उद्योगों के स्वॉट विश्लेषण पर भी विशेष बल दिया गया है।

बीज शब्द– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, नाबार्ड, उत्तराखंड।

Challenges and Opportunities of Food Processing Industries in India-with special reference to initiatives of NABARD in Uttarakhand

Preeti Pant
Assitant Professor, Deptt. of Commerce
B.S.N.V. P.G. College, Lucknow-226001. U.P., India
preetipant@gmail.com

Abstract- India is the world's second largest producer of food next to China yet only accounts for 1.5% of total worldwide food trade. This indicates vast scope for both investors & exporters. Food processing industry is of enormous significance in this context because of the vital linkages & synergies that it promotes between the two pillars of our economy, industry & agriculture. The industry contributes 32% to the country's total food market & is ranked fifth in terms of production, consumption, export & expected growth. Having great export advantage, processed food products accounts for 13% of India's exports. Being an agricultural economy the sector also contributes largely towards rural development of India which is core of our national development. Recognizing the fact, *National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD)* is providing several initiatives for these industries. These initiatives have relatively greater scope in Uttarakhand which suffered extensive damage in the 2013 deluge. This paper is an attempt to evaluate critically & analytically the drivers & potential barriers to growth of the sector with special reference to initiatives of NABARD in UIttarakhand state. Special emphasis is made on SWOT analysis & thrust areas for future for achieving greater role of the sector in the national economy.

Key words- Food processing industries, NABARD, Uttarakhand.

1. **प्रस्तावना**– भोजन मानवीय आवश्यकताओं का आधार है। मनुष्य को भोजन प्रकृति से प्राप्त है, परन्तु समाज के विकास के साथ–साथ मनुष्य ने पशुओ को मारकर खाने के स्थान पर कृषि करना भी प्रारम्भ किया। मनुष्य के सभ्य होने के साथ, भोजन को हर समय उपलब्ध कराने के लिये खाद्य संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार मनुष्य खाद्य सामग्रियों के संरक्षण की विभिन्न विधियों के प्रति आकर्षित हुआ। समय बीतने के साथ खाद्य सामग्रियों को संरक्षित रखने की अनेक परिष्कृत विधियों का जन्म हुआ। बढती हुई जनसंख्या के भार ने भी खाद्य संरक्षण को और प्रभावी बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसलिए उपलब्ध भूमि, सौर ऊर्जा व जल संसाधन के लाभों को अधिकतम बनाने के लिए कृषि में आधुनिक व्यवस्थित व वैज्ञानिक विधियों के प्रयोगों पर जोर दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण से आशय उन तकनीकियों व आर्थिक क्रियाओं के समूह से है जो किसी भौतिक या रासायनिक माध्यम से कच्ची सामग्री को भोजन अथवा भोजन को किसी अन्य रूप में रूपान्तरित करें। खाद्य प्रसंस्करण कच्ची सामग्रियों(जैसे–कृषि जनित उत्पाद, पशु उत्पाद, मत्स्य उत्पाद, एवं वन जनित उत्पादों) के संरक्षण, विनिर्माण व उपयोगिता वर्धन से संबंधित हैं। जिसमें किसी प्रक्रिया(कर्मचारी, बिजली, मशीन और पूंजी को शाामिल करते हुए) द्वारा इन्हें इस प्रकार रूपांतरित किया जाता है कि इनके मूल वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन आ जायें, रूपांतरित पदार्थ उपभोग योग्य खाद्य सामाग्री, तन्तु, ईधन या कच्चे माल के रूप प्रयुक्त किया जा सके, व इसका कोई वाणिज्यिक मूल्य हो।

कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र आपस में निकटतम सम्बन्ध रखते हैं। दोनों क्षेत्रों में दो प्रकार के सम्बन्ध हैं– अग्रगामी व अधोगामी। जहाँ कृषि उद्योगों को खाद्य सामग्री, कच्चा औद्योगिक माल एवं निर्यात संवर्धन लाभ प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर उद्योग कृषि को विभिन्न कृषि आगत(इनपुट) प्रदान करते हैं। इस सन्दर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पशु व खाद्य उत्पादों में मूल्य संवर्धन करके उन्हें पोषण, आहार, एवं विकास के लिए तैयार किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण कृषि व उद्योगों में पार्श्व सम्बन्ध भी स्थापित करते हैं। इन उद्योगों से निकलने वाले संलग्न एवं अवशिष्ट सामग्री अन्य प्रक्रियाओं में प्रयुक्त की जाती है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने वाले उद्योग विभिन्न अवशिष्टों के रूप मे ईंधन, रसायन, एवं उपयोगी लुगदी उत्पादित करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सामान्यतः तीन वर्गों मे विभाजित किए जा सकते हैं– प्राथमिक, असंगठित, एवं संगठित। (सारिणी–1)

सारिणी–1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का वर्गीकरण

क्र0 सं0	आधार	प्राथमिक	असंगठित	संगठित
1.	क्षेत्र	ग्रामीण, दूरस्थ, आदिवासी, या शहरों से निकट	ग्रामीण या कस्बे	बड़े शहरों मे
2.	वित्तीय स्थिति	कमजोर	आवश्यक वित	समुचित वित्त सुविधायें
3.	निर्मित वस्तुएं	परम्परागत	परम्परागत व गैर–परम्परागत दोनों	गैर परम्परागत
4.	मशीनीकरण	नहीं के बराबर	निम्न स्तर	उच्च स्तर
5.	संरक्षण की विधियां	पूर्णतया परम्परागत	आधुनिकता के नजदीक	पूर्णतया आधुनिक
6.	उदाहरण	चक्की, चावल, दाल, तेल इत्यादि की मिलें	फलों व सब्जियों का प्रसंस्करण, डेयरी इत्यादि	चॉकलेट, पेय पदार्थों, फास्ट फूड इत्यादि
7.	प्रसंस्करण के चरण	प्राथमिक	सामान्यतः द्वितीयक	सामान्यतः अन्तिम

इन तीन वर्गों मे विभाजन का कोई ठोस आधार नहीं है क्योंकि अनेक क्षेत्रों मे संगठित औद्योगिक ईकाइयों का योगदान निरन्तर बढ रहा है। डेयरी में असंगठित क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है व भविष्य में शहरों में संगठित क्षेत्र का योगदान के बढ़ने की उम्मीद है। फलों व सब्जियों के प्रसंस्करण में दोनों का बराबर योगदान है वहीं मांस व मत्स्य प्रसंस्करण में असंगठित क्षेत्र का व पैकेजड् फूड में संगठित क्षेत्र का अधिक योगदान है। प्रसंस्करण कोई क्रिया नही अपितु अनेक क्रियाओं का क्रमबद्ध समूह है।(सारिणी–2)

सारिणी–2: खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया के चरण

उत्पाद	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक
अनाज व दलहन	छँटाई व ग्रेडिंग	आटा, धान, पफ, माल्ट व मिलिंग	बिस्कुट, नूडल्स, कार्नफ्लेक्स्, नमकीन, केक, एल्कोहल
फल व सब्जियां	सफाई, छँटाई, ग्रेडिंग, व कटाई	स्लाइस्, गूदा, फ्लेक्स्, पेस्ट, प्रसंस्कृत व फ्लेवरड् उत्पाद	कैचप, जैम, जूस, अचार, कैन्डी, स्नैक्स, व अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद
तिलहन	छँटाई व ग्रेडिंग	आईल केक	सरसों, सूरजमुखी, जैतून, सोयाबीन, मूँगफली इत्यादि का तेल

मसालें	सफाई, सुखाना, ग्रेडिंग, छँटाई	कुटाई, पिसाई, व छनाई	रेडी टू यूज उत्पाद
बेवरेज्स् (पेय पदार्थ)	छँटाई, ब्लीचिंग, व ग्रेडिंग	पत्ते, धूसी, व पाउडर	चाय पत्ती, टी बैग, फ्लेवरड् कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एल्कोहलिक पेय पदार्थ
दूध	ग्रेडिंग व रेफ्रीजिरेटिंग	कॉटेज चीज, क्रीम, स्किम्ड् व ड्राइड मिल्क	मक्खन, दही, घी, आईसक्रीम, संघनित दूध, स्किम्ड् दूध, चीज, दूध पाउडर
मांस व पोल्ट्री	छँटाई, व रेफ्रीजिरेटिंग	कटा, तला, फ्रोजन, व चिल्ड्	रेडी टू ईट उत्पाद
समुद्री उत्पाद	फ्रीजिंग व चिलिंग	कटा, तला, फ्रोजन, व चिल्ड्	रेडी टू ईट उत्पाद

2. **खाद्य प्रसंस्करण का इतिहास–** खाद्य प्रसंस्करण का इतिहास मनुष्य के इतिहास जितना ही प्राचीन है। पुरातन काल में मनुष्य प्राथमिक प्रसंस्करण प्रक्रियाओं के रूप में खमीर चढाना, सौर ऊर्जा द्वारा सुखाना, नमक संरक्षण व विभिन्न प्रकार की पाक विधियों; जैसे–भाप से पकाना, धुँए से पकाना, भूनना, सेंकना इत्यादि का प्रयोग करता था। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उद्योगों में सेना की बढती हुई मांगों के कारण मशीनीकरण एवं व्यवसायीकरण का उदय हुआ। विभिन्न औद्योगिक क्रान्तियों व द्वितीय विश्वयुद्ध ने इस नवीन प्रयोग को उचित बढावा दिया। इसके फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक सामान्य खाद्य प्रसंस्करण की औद्योगिक इकाइयों का जन्म हुआ। इसमें जलीय ऊर्जा चलित चक्की, कोल्हू चलित तेल घानी, कोल्हू से गन्ना निचोड़ने वाली मशीन, कताई वाली मशीन, चरखा, हस्तकरघा इकाई इत्यादि प्रमुख हैं।[1] बीसवीं शताब्दी में अन्तरिक्ष युग व विकसित होते उपभोक्ता समाज ने खाद्य प्रसंस्करण में नवीन प्रौद्योगिकी व तकनीकियों को विकसित किया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सन् 1863 में मद्रास के गवर्नर सर विलियम डेनिसन ने कृषि व प्रसंस्करण उद्योगों पर विशेष ध्यान देने के सन्दर्भ में एक पत्र लिखा, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड से आधुनिक व नवीन तकनीक वाली मशीनें प्रदर्शन व अंगीकरण किए जाने के लिए भारत मंगवाई गयीं। इस काल मे चावल के प्रसस्करण से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की शुरूआत की गयी जिसके पश्चात् गेंहूँ मिल, पेपर व लुग्दी उद्योग, दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग, जूट उद्योग, गन्ना प्रसंस्करण व तेल निकालने वाले संयन्त्र लगाये गये। परन्तु प्रसंस्करण की वास्तविक महत्ता बंगाल की सन् 1870 की त्रासदी के पश्चात् परिलक्षित हुई। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के महानायकों ने भी प्रसंस्करण से भारतीयों को जोड़ने का प्रयास किया। खाद्य प्रसंस्करण को ग्रामीण विकास का 'पूर्ण स्वराज' का महत्वपूर्ण यंत्र मानते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने "चरखा" को सन् 1930 के दौरान प्रोत्साहित किया। गाँधी जी का नमक सत्याग्रह भी प्रसंस्करण क्रियाओं को बढावा देने के लिए था। उनके अनुचरों जैसे नरहरी भावे, विनोबा भावे, जय प्रकाश नारायण इत्यादि ने भी प्रसंस्करण क्रियाओं को खादी व ग्रामाद्योगों मे प्रोत्साहित किया।

भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जैसे–जैसे सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढावा दिया वैसे–वैसे प्रसंस्करण उद्योगों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, इस काल में 1980 के दौरान एक नयी स्फूर्ति का सृजन हुआ जब हरित क्रान्ति के माध्यम से कृषि में आशातीत वृद्धि हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1950–51 में उत्पादकता 0.522 टन प्रति हेक्टेयर थी जो 1967–68 में हरित क्रान्ति के आगमन तक 20.49 % बढ़कर 0.629 टन हेक्टेयर हो गयी। हरित क्रान्ति के प्रारम्भिक प्रसार के दौरान 1968–69 से 1985–86 तक यह उत्पादकता 50% बढ़कर 1.175 टन प्रति हेक्टयर हो गयी। इसके पश्चात् व्यापक प्रसार के चरण में मात्र अगले 10 वर्षों में कृषि उत्पादकता में 43% की बढ़त हुई जो अत्यन्त सराहनीय है। इसके बाद अगले 9 वर्ष हरित क्रान्ति युग के सबसे खराब वर्ष थे जिसके दौरान उत्पादकता में मात्र 10% की बढ़त हुई। उत्पादकता की वृद्धि दर में यह कमी कृषि संसाधनों के अन्य क्षेत्रों में प्रतिस्थापन के कारण थी। 2006–07 से 2012–13 के मध्य कृषि क्षेत्र ने पुर्नवापसी करते हुए 21.17% की उत्पादकता वृद्धि प्राप्त की है।[2]

इस संदर्भ मे सन् 1990 की उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीति भी महत्वपूर्ण है जिसने इस क्षेत्र में जहाँ एक ओर घरेलू उद्योगों को उदार नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया, वहीं दूसरी ओर वैश्विक नीतियों द्वारा विदेशी औद्योगिक ईकाइयों को विनियोगों के लिए आकर्षित किया। वर्तमान समय में खाद्य प्रसंस्करण भारत के माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया अभियान' के अर्न्तगत एक प्राथमिकता क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के प्रयोजन से सरकार सशक्त कृषि संसाधन आधार वाले क्षत्रों मे साधारण सुविधायें जैसे–सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, सीवेज सुविधा व प्रसंस्करण सुविधायें जैसे–पल्पिंग, पैकेजिंग, शीत भंडारण व लॉजिस्टिक्स के साथ मेगा फूड पार्क विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त सरकार के 'स्टार्ट अप इण्डिया' व 'स्किल इण्डिया' अभियान भी उद्यमिता व कौशल विकास के द्वारा इन उद्योगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभान्वित कर रहे हैं।

3. **भारत में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति–** भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है इस संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुपयोगी है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तम्भों–कृषि व उद्योगों में प्रभावी सहसम्बन्धों का निर्माण करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बाजार विस्तार के माध्यम से कृषि उपज को भी प्रोत्साहित करते हैं व उपयोगिता सृजन द्वारा कृषकों की आय बढाने में भी सहायक हैं। इन उद्योगों के फलस्वरूप कृषि में तकनीक विकास व नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण

उपलब्ध होता है। प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण की क्रियाओं को लघु, सूक्ष्म व मझोले उपक्रमों के माध्यम से स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रभावी रोजगार सृजन भी किया जा सकता है। यह कच्चे खाद्य सामग्री, मशीन, यंत्र, संवेष्ठन सामग्री व द्वितीयक प्रसंस्करित सामग्रियों की मांग बढाने में भी सहायक है। खाद्य प्रसंस्करण न केवल राष्ट्रीय अपितु अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकानेक अवसर उत्पन्न करता है। पोषण, आहार, व विकास की दृष्टि से उत्तम प्रसंस्कृत उत्पादो के लिए भारत में बदलती उपभोक्ता जीवन शैली, रूचियां व अभिरूचियां एक नये बाजार का सृजन करती हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन् 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, सन् 1986 में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण, व जुलाई 1998 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की। यह मंत्रालय समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं व उद्देश्यों के अंतर्गत इन उद्योगों के लिए नीतियों व योजनाओं के प्रतिपादन व कार्यान्वयन का कार्य करता है। सरकार के विजन 2020' योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को दूसरा सर्वाधिक रोजगार संभावना वाला क्षेत्र चिन्हित किया गया हैं।[3] सरकार के अथक प्रयासों व भारतीय समाज व उपभोक्ताओं के प्रगतिशील व आकांक्षित दृष्टिकोण से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है। इन सुधारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–(सारिणी–3)

सारिणी–3: भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का बदलता परिदृश्य

बदलता परिदृश्य	उल्लेखनीय तथ्य
भारत में कृषि अभी भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है।	भारतीय कृषि का जी0डी0पी0 में 16.1% का योगदान है। यद्यपि यह घटा है तथापि विश्व औसत कृषि उत्पादन योगदान (6%) से कहीं ज्यादा है।[4]
खाद्य उद्योगों का विकास के आधार पर भविष्य बेहतर है।	खाद्य बाजार, जो वर्तमान में 39.71 बिलियन यू0एस0 डालर है, के 11% की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर से 65.4 बिलियन यू0एस0 डालर होने की संभावना है।[5]
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारतीय खाद्य बाजार का अभिन्न अंग है।	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के कुल खाद्य बाजार का 32% है एवं उत्पादन, उपभोग, निर्यात एवं भावी वृद्धि के आधार पर पाँचवा स्थान रखता है।(आई0बी0ई0एफ0)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है।	यह उद्योग भारत के कुल औद्योगिक विनियोगों का 6% है ।
यह उद्योग भारत के जी0डी0पी0 का एक बडा हिस्सा है।	यह उद्योग निर्माणात्मक जी0डी0पी0 का 14% है ।
यह उद्योग भारत के निर्यातों में बडी हिस्सेदारी रखता है।	प्रसंस्करित उत्पाद, भारतीय निर्यातों का 13% है।
भारतीय खाद्य बाजार वैश्विक खाद्य बाजार में अपनी पैठ बना चुका है।	भारतीय खाद्य बाजार, विश्व का ***छठां*** सबसे बडा बाजार है।
बढता हुआ वैश्वीकरण, भारत के विश्व व्यापार के लिए हितकारी है।	भारत अपने निर्यातों को 2019–20 तक दोगुना करके 900 बिलियन यू0एस0 डालर तक करने के लिए प्रयासरत है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बडी मात्रा को आकर्षित करने में सफल हुए हैं।	अप्रैल, 2016 से सितम्बर, 2017 तक इस क्षेत्र में 500.77 मिलियन यू0एस0 डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है।[6]
भारतीय सरकार इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है।	सरकार ने भारत में निर्मित या उत्पादित प्रसंस्करित उत्पादों के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की घोषणा की है।
भारतीय आनलाइन खाद्य बाजार उद्योगो में नए अवसर प्रदान कर रहा है।	भारतीय उपभोक्ताओं का "रेडी टू ईट" उत्पादों के प्रति रूझान बढ रहा है। जोमाटो रेस्टोरेन्ट सर्च एवं डिस्कवरी सर्विस के सर्वे के अनुसार मात्र 8 माह में 14 शहरों में लगभग 10 लाख से अधिक व्यक्तियों ने आनॅलाइन फूड आर्डर दिए। उपभोक्ताओं की खाद्य सम्बन्धी आदतों में बहुत बडा बदलाव देखा गया है। दोहरे आय स्तर, जीवन शैली व सुविधा के संदर्भ में लगभग 79% लोग "रेडी टू ईट" भोजन को प्राथमिकता देते है।(ऐसोचैम)

विगत कुछ वर्षों मे भारत में कृषि उत्पादन में निरंतर उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता व आम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, व चावल, गेंहूँ, सब्जियों व बागवानी उत्पादों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।[7] कच्चे माल की प्रचुर आपूर्ति, खाद्य उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि, सरकार का प्रगतिवादी दृष्टिकोण, व बदलते सामाजिक परिवेश का खाद्य प्रसंस्करण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार व निवेश के एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर उभरा है।(सारिणी–4)

सारिणी–4: खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा सकल मूल्य वर्धन (समव) (चर 2011–12 के मूल्यों पर) रुपए लाख करोड़ में

क्र0सं0	आर्थिक क्रिया	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	समव–संपूर्ण भारत	81.07	85.47	90.84	97.27	104.27
2.	समव–विनिर्माण	14.10	14.95	15.80	16.67	18.22
3.	समव–कृषि, वानिकी, व मत्स्य पालन	15.02	15.24	15.88	15.84	16.04
4.	समव–खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1.47	1.33	1.35	1.43	1.53
	वृद्धि दर (%)					
	आर्थिक क्रिया	**ए0ए0जी0आर0**	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**
5.	समव–संपूर्ण भारत	6.50	5.43	6.29	7.08	7.19
6.	समव–विनिर्माण	6.63	6.05	5.65	5.53	9.29
7.	समव–कृषि, वानिकी, व मत्स्य पालन	1.67	1.50	4.19	–.025	1.25
8.	समव –खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1.18	–9.69	1.91	5.78	6.71
	सकल मूल्य वर्धन मे योगदान (%)					
	आर्थिक क्रिया	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**
9.	समव –खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1.81	1.55	1.49	1.47	1.46
10.	समव–विनिर्माण	17.39	17.50	17.39	17.14	17.47
11.	समव–कृषि, वानिकी, व मत्स्य पालन	18.53	17.84	17.48	16.29	15.38
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का योगदान (%)					
8.	समव–विनिर्माण	10.42	8.87	8.56	8.58	8.37
9.	समव–कृषि, वानिकी, व मत्स्य पालन	9.78	8.70	8.51	9.03	9.51

स्रोत–वार्षिक प्रतिवेदन (2016–17), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार[8]

जैसा की उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से प्रगति पर है। यह सकल मूल्य वर्धन में कृषि व विनिर्माण क्षेत्रों की तुलना में अधिक उच्चतर स्तर पर है। यह इकाइयां स्वभावतः अत्यंत श्रम सघन व कम सघन पूंजी निवेश वाली हैं। इनमें स्थिर पूंजी से उत्पादन का अनुपात 0.19 है जो यह दर्शाता है कि कीमत के संदर्भ में, अन्य श्रम सघन उद्योगों की तुलना में इनकी एक इकाई के उत्पादन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह इकाइयां उद्यमिता(कम पूंजी) के साथ–साथ अभूतपूर्व रोजगार अवसरों का भी सृजन करती है(सारिणी–5)। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2013–14 के अनुसार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भारत के सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाले उद्योग है। 2013–14 में 11.69% रोजगार सृजन के साथ किया इन उद्योगों ने विगत पांच वर्षो मे 2.25% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से रोजगार सृजन किया है।

सारिणी–5: पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की मुख्य विशेषताएं: (1998–99 से 2013–14)

वर्ष	रोजगार (लाख)	वृद्धि (%)	स्थिर पूंजी (करोड़ रुपए)	वृद्धि (%)	वर्ष	रोजगार (लाख)	वृद्धि (%)	स्थिर पूंजी (करोड़ रुपए)	वृद्धि (%)
1998–99	13.46	–	26756	–	2006–07	14.76	6.03	57460	26.68
1999–00	13.47	0.07	31642	18.26	2007–08	15.05	1.96	68335	18.93
2000–01	13.33	–1.04	31887	0.77	2008–09	15.64	3.92	81156	18.76
2001–02	13.07	–1.95	33907	6.33	2009–10	16.06	2.69	99482	22.58
2002–03	13.08	0.08	37627	10.97	2010–11	16.62	3.49	120705	21.33
2003–04	12.97	–0.84	37412	–0.57	2011–12	17.77	6.92	145038	20.16
2004–05	13.43	3.55	41388	10.63	2012–13	16.89	–4.95	158865	9.53
2005–06	13.92	3.65	45357	9.59	2013–14	17.41	3.08	168380	5.99

स्रोत–वार्षिक प्रतिवेदन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न अंकों द्वारा संकलित

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां न केवल घरेलू बाजार मे अपितु वैश्विक बाजार में भी अपनी पैठ बना रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां सामान्यतः निर्यातोन्मुख इकाइयां हैं। भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख प्रसंस्कृत उत्पादों में *आम का गूदा, सूखी व प्रसंस्कृत सब्जियां, मूंगफली, कन्फेक्शनरी, कोकोआ, अल्कोहलिक व गैर अल्कोहलिक पदार्थ* इत्यादि है।[9] वर्ष 2015 में कुल वैश्विक खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात में भारत का योगदान 2.36% का था (ट्रेड मैप)[10]। इसलिए विदेशी निवेशक भी इस क्षेत्र में अपना रूझान दिखा रहे हैं(चित्र–1)। इस संदर्भ मे भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए स्वचालित

मार्ग पर 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त भारत मे निर्मित या/और उत्पादित खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के व्यापार (ई–कामर्स सम्मिलित) के लिए अनुमोदन मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी हैं।

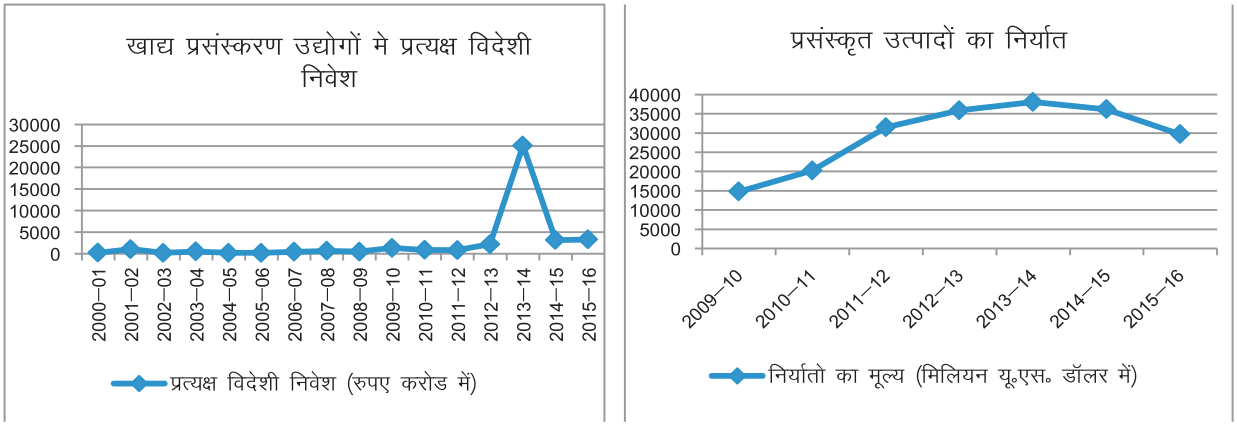

चित्र–1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विदेशी व्यापार व विदेशी विनियोग

शोधकर्ता ने भारत की प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का भी एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया हैं**(सारिणी–6)**। इनमें से पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की सफलता की कहानी अत्यन्त प्रेरणात्मक है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड व आईटीसी की वार्षिक आय क्रमशः 630 मिलियन यू0एस डालर (2015–16) व 1.6 बिलियन यू0एस0 डालर रही, जो अत्यन्त सराहनीय है।

सारिणी–6: भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मुख्य औद्योगिक इकाइयाँ

कम्पनी का नाम	क्षेत्र	विनिर्मित उत्पाद	प्रमुख ब्रान्ड
आई0टी0सी0 लिमिटेड	खाद्य उत्पाद	बिस्कुट, रेडी टू ईट स्नैक्स	बिंगो, सनफीस्ट, कैन्डी
पार्ले प्रोटक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	कन्फेक्शनरी व खाद्य उत्पाद	चॉकलेट, बिस्कुट	पार्ले जी, क्रैक–जैक, मोनाको, हाईड एण्ड सीक, पार्ले मारी, बोरबॉन, मैलोडी, मैंगो बाइट, पार्ले रस्क, इक्लेयर्स, कच्चा खट्टा
गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड	डेयरी	दूध, मक्खन, दही, घी, आईसक्रीम	अमूल
पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड	डेयरी	दूध, मक्खन, दही, घी, डेयरी वाईटनर इत्यादि	पराग
परफैटी वैन मीलै इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	कन्फेक्शनरी व गम केयर	चॉकलेट, माउथ फ्रैश	एलपेनलीबे, मैन्टोस, सेन्टर फ्रैश, बिग बबूल, क्रीमफिल्स, क्लोरोमिन्ट
कैडबरी इण्डिया लिमिटेड	कन्फेक्शनरी	चॉकलेट, शेक पाउडर	डेयरी मिल्क, पर्क, फाइव स्टार, जेम्स, सैलीब्रेशन, सिल्क टेम्पटेशन
पतन्जलि आयुर्वेद लिमिटेड	कन्फेक्शनरी, पेय पदार्थ, स्नैक्स, हेल्थ सप्लिमेन्ट	घी, च्वयनप्राश, बादाम पाक, शहद, जूस, मंजन, औषधि इत्यादि	पतन्जलि
पेप्सीको इण्डिया	पेय पदार्थ व स्नैक्स	सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, नमकीन, ओट्स	पेप्सी, सेवन अप, एक्वाफिना, चीटोज्, ड्यूक, कुरकुरे, लेज्, लहर, स्लाइस, माउन्टेन ड्यू, ट्रौपिकाना, अंकल चिप्स, मिरिन्डा
द कोका–कोला कम्पनी	पेय पदार्थ	सॉफ्ट ड्रिंक्स	कोका–कोला, माजा, फेन्टा, किन्ले, कोक, स्प्राइट, लिम्का
नेस्ले इण्डिया लिमिटेड	कन्फेक्शनरी, डेयरी, बौटल्ड् वाटर, हेल्थ केयर न्यूट्रीशन	शिशु आहार, चाकलेट, स्नैक्स, कॉफी, फ्रोजन फूड	नेस्ले, नेस्कैफे, बूस्ट, सैरेललेक, लेक्टोजन, मैगी

	आईसक्रीम		
ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज	खाद्य उत्पाद व डेयरी	बिस्कुट, रस्क, ब्रेड, केक, गिफ्ट खाद्य उत्पाद, मक्खन, घी, दूध, चीज, डेयरी वाईटनर	टाईगर, मिल्क बिकीज्, गुड डे, ट्रीट, 50–50, लिटिल हार्टस्, बोरबोन,
हिन्दुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड	खाद्य उत्पाद, पेय पदार्थ, ओरल केयर	जैम सूप, कॉफी, चाय, आईसक्रीम, मंजन	नॉर, क्वालिटी वाल्स, किसान मैग्नम ब्रू, लिप्टन, ब्रुक बाण्ड, रेड लेबल, ताजा, ताज महल, मैग्नम, पेप्सोडेन्ट, अन्नपूर्णा,
मोहन मीकिन लिमिटेड	पेय पदार्थ (एल्कोहलिक व गैर एल्कोहलिक)	बियर, रम, विस्की, ब्रैन्डी, जूस, मिनरल वाटर, सिरका	ओल्ड मांन्क, मोहन, लॉयन बियर
मैवली टिफिन रूमस् फूड्स लिमिटेड	खाद्य उत्पाद	इन्स्टेन्ट प्री मिक्सड, उत्पाद, अचार, मसाले	एम0टी0आर0
गिट्स फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	खाद्य उत्पाद	इन्स्टेन्ट प्री मिक्सड, उत्पाद, स्नैक्स	गिट्स
डाबर इण्डिया लिमिटेड	खाद्य उत्पाद, हेल्थ सप्लीमेंट व ओरल केयर	शहद, जूस, दवाइयां, च्वयनप्राश, डाइजेस्टिव्स, मंजन	डाबर
टाटा ग्लोबल बेवरेज्स् लिमिटेड	खाद्य उत्पाद व पेय पदार्थ	चाय, कॉफी, नमक, मिनरल वाटर	हिमालयन, टाटा, टेटली
वेन्कीस् (इण्डिया) लिमिटेड	माँस व पोल्ट्री	चिकन व मांस प्रसंस्करण (पोल्ट्री व घरेलू दोनो प्रयोगो के लिए)	वेन्कीस्
यूनाइटेड ब्रियूरीस् लिमिटेड	एल्कोहलिक पेय पदार्थ	एल्कोहलिक पदार्थ	किंगफिशर
कर्नाटका मिल्क फेडीरेशन	डेयरी	दूध, आईसक्रीम, मक्खन, घी, दही	के0एम0एफ0
अल्काबीर फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	माँस व पोल्ट्री	चिकन व मटन	अल्काबीर
डेलमोन्टे फूड्स	खाद्य उत्पाद, पेय पदार्थ, पोल्ट्री	कैन्ड फ्रूट व वेजीटेबल्स, सॉस, जूस, सिरका	डेलमोन्टे
हल्दीरामस्	कन्फेक्शनरी, पेय पदार्थ, डेयरी	कैन्ड फ्रूट, कुल्फी, स्वीट्स, स्नैक्स	हल्दीरामस्

4. **उत्तराखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नाबार्ड द्वारा की जा रही पहल–** उत्तराखंड, 9 नवम्बर, 2000 को भारत गणराज्य का सत्ताइसवां राज्य घोषित किया गया। 86% पर्वतीय भाग से आच्छादित यह राज्य भारत का दूसरा सर्वाधिक विकास करने वाला राज्य है। इसी क्रम में 2011–12 से 2015–16 के मध्य राज्य की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर 7% रही। सकल राज्यीय घरेलू उत्पादन (2015–16) में प्राथमिक, द्वितीयक, व तृतीयक क्षेत्र का योगदान 11.6: 51.2: 37.2 हैं। पर्वतीय क्षेत्रों मे तीखे ढलान व भू–क्षरण के कारण प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटा है फिर भी कृषि राज्य के 45% श्रमिकों का प्रमुख व्यवसाय है। राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं जो मुख्यतः कृषि पर आधारित है। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों व विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों से सुसज्जित इस राज्य में औषधीय व सुगंधीय पुष्पोत्पादन, जैविक कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि विपणन इत्यादि के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इस संदर्भ मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग न केवल उपलब्ध कृषि उपज का सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं अपितु जीविकोपार्जन के लिए औद्योगिक विकल्प भी प्रदान करते हैं। राज्य में 2013–14 में कुल 380 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां थी। राज्य में लीची, हॉर्टीकल्चर, औषधीय व सुगंधीय पुष्प, व बासमती चावल के लिए एग्रो निर्यात जोन की भी स्थापना की गयी है।

सारिणी–7: उत्तराखंड के प्रमुख कृषि उत्पादों में प्रसंस्करण के सम्भावित क्षेत्र

वर्ग	उत्पाद	**सम्भावित प्रसंस्कृत उत्पाद**
अनाज	गेंहूँ	आटा, मैदा, सूजी, इन्टेन्ट फूड, बेकरी उत्पाद
	जौ	बीयर
	मक्का	स्टार्च, कार्नफ्लेक्स, मक्के का तेल

	धान	चावल, चावल की भूसी
	गन्ना	चीनी, गुड, मिश्री, खण्डसारी, एल्कोहल
फल	आम	चटनी, जैम, जूस, अचार, गूदा, व स्क्वैश
	लीची	जूस, गूदा, व स्क्वैश
	सेब	मुरब्बा, जैम, जूस, जैली, गूदा, व स्क्वैश
सब्जियां	टमाटर	प्यूरी, अचार, जैली, पेस्ट, कैचप, सॉस, सूप, चटनी, पाउडर
	आलू	फ्लेक्स, चिप्स
	मशरूम	मशरूम का प्रीर्जवेशन, व संवेष्ठन
	प्याज	अचार, फ्लेक्स, पाउडर
मसालें	मिर्च	पेस्ट, तैली राल
	लहसुन	फ्लेक्स, पाउडर, निर्जलीकृत लहसुन
	अदरक	पाउडर, पेस्ट, तैली राल, अचार, स्क्वैश
	हल्दी	पाउडर, अचार
तेल	सरसों	तेल, सोयासॉस
	सोयाबीन	सोयाफ्लोर, सोयामिल्क
	मूंगफली	प्रोटीन आइसोलेट, लिसिथिन
दूध	दूध	दूध पाउडर, मक्खन, दही, घी, आईसक्रीम, चीज, पनीर, खोया
माँस व पोल्ट्री	मांस व अंडे	प्रसंस्कृत माँस, अंडे, पोल्ट्री उत्पाद (बेकरी उत्पाद)

प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर वर्ष 2013 के भीषण जल प्रलय, के कारण भारत सरकार ने राज्य को 'प्राकृतिक आपदा ग्रस्त क्षेत्र' की सूची व *नेशनल ऐक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज* में शामिल किया है। इसलिए तेरह जिलों के इस राज्य में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का वर्तमान व अल्पकालीन लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनो, उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रचर सुविधाओं, बाजार प्रवृत्ति, जन कौशल, बजटरी अनुदान, सरकार की प्राथमिकताएं व नीतियां, साख वितरण तन्त्र के आधार पर नाबार्ड ने 2017–18 के लिए 18663.72 करोड रूपए की ऋण संभाव्यता का आंकलन किया हैं। खाद्य प्रसंस्करण को विकास की प्राथमिकता मे रखते हुए भारत सरकार ने फूड पार्क, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण व वित्त प्रदान करने हेतु 2014–15 के बजट मे नाबार्ड के साथ 2000 करोड रूपए का एक विशेष कोष का निर्माण किया है।[11] इसका मुख्य उददेश्य कृषि उपज की बर्बादी को कम करना व रोजगारों का सृजन करना है। उत्तराखंड में दो फूड पार्क है जिनमें से समस्त सुविधाओं से सम्पन्न पतन्जलि मेगा फूड पार्क भारत का सबसे बडा फूड पार्क है। 31 जनवरी, 2017 तक नाबार्ड ने राज्य में मेगा फूड पार्कों व व्यक्तिगत इकाइयों के लिए 464.49 करोड रूपयों का सावधि ऋण प्रदान किया है।[12] कृषि, बागवानी(हॉर्टीकल्चर), डेयरी, पोल्ट्री, व फिशरीज् यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं इसलिए शोधकर्ता ने इन सभी क्षेत्रों मं उत्तराखंड में जिलानुसार संभावनायें व नाबार्ड द्वारा इन क्षेत्रों के लिए प्रदान किए गए पोटेंशियल लिंकड् केडिट प्लान का प्रयोग किया है(सारिणी–7 व 8)।

सारिणी–8: उत्तराखंड के जिलों मे क्षेत्रानुसार संभावनायें(नाबार्ड द्वारा चिन्हित)

जिले	क्षेत्र व संभावनायें
अल्मोड़ा	डेयरी–हवालबाग, लमगडा, भैंसियाछिना, डौलादेवी, ताकुला, द्वाराहाट, व ताड़ीखेत, बकरीपालन–हवालबाग, लमगडा, भैंसियाछिना, डौलादेवी, ताकुला, सल्ट, स्याल्दे, व भिकियासेंण, बेमौसमी सब्जियाँ–रानीखेत
बागेश्वर	डेयरी–कपकोट, गरूड, व बागेश्वर, बकरीपालन–कपकोट व बागेश्वर
चमोली	खाद्य व सब्जियों का प्रसंस्करण, भेड़ व बकरी पालन–कर्णप्रयाग व घाट
चम्पावत	डेयरी विकास, व भेड़ व बकरी पालन–चम्पावत व लोहाघाट
देहरादून	डेयरी विकास, हॉर्टीकल्चर, पॉली हाउस, फूलबानी, व मशरूम व अदरक की खेती–प्रत्येक ब्लॉक
हरिद्वार	डेयरी विकास, व आम व चिनार का उत्पादन–लश्कर, व बहादुराबाद
नैनीताल	डेयरी विकास व हॉर्टीकल्चर(सेब, आम व प्लम)–रामनगर व कोटाबाग
पौड़ी गढ़वाल	सब्जियों का क्लस्टर–नैनीडंडा
पिथौरागढ़	डेयरी विकास व भेड़, बकरी व खरगोश पालन–मुंश्यारी, बिन, ततरा जौहर, मूनाकोट
रूद्रप्रयाग	सब्जियों का क्लस्टर, हॉर्टीकल्चर (आम, अखरोट, व प्लम)–संपूर्ण जिला
टिहरी गढ़वाल	सब्जियों का क्लस्टर, हल्दी व अदरक, भेड व बकरी पालन–जौनपुर
उधमसिंह नगर	डेयरी विकास व बकरी पालन (माँस के लिए)– संपूर्ण जिला
उत्तरकाशी	सेब व मशरूम की खेती, भेड़ व बकरी पालन– संपूर्ण छः ब्लॉक

स्रोत–स्टेट फोकस पेपर, नाबार्ड, उत्तराखंड

सारिणी–9: उत्तराखंड के जिलों मे क्षेत्रानुसार क्षमतायुक्त क्रेडिट प्लान(2017–18)

जिले	फूड प्रोसेसिंग	फसली ऋण	हॉर्टीकल्चर	डेयरी	पोल्ट्री	फिशरीज्
अल्मोड़ा	679.84	11349.73	229.22	3067.44	427.24	46.08
बागेश्वर	354.48	4253.77	92.64	1174.55	118.88	20.16
चमोली	2114.55	4518.10	311.89	3165.15	101.88	22.28
चम्पावत	270	6246.57	506.72	914.32	234.94	58.81
देहरादून	3452.22	27902.27	7111.31	10404.11	3929.94	278.60
हरिद्वार	4895.27	190328.30	3003.54	13583.43	905.75	218.69
नैनिताल	6698.425	43006.21	3224.47	7357.81	1822.16	134.26
पौड़ी गढ़वाल	2335.5	6008.06	698.05	1636.79	409.27	24.07
पिथौरागढ़	344.06	18553.46	493.79	1277.25	236.99	62.08
रूद्रप्रयाग	94.95	9017.81	585.26	1784.14	75.78	9.69
टिहरी गढ़वाल	158.22	12637.94	1433.52	5264.82	595.44	43.76
उधम सिंह नगर	65267.55	295085.4	2297.10	21894.33	3653.57	1106.31
उत्तरकाशी	200.99	11179.24	443.23	1332.81	104.26	25.94
कुल योग	86866.06	640086.9	20430.74	72856.95	12616.10	2050.73

स्रोत–स्टेट फोकस पेपर (2017–18), नाबार्ड, उत्तराखंड

राज्य की असीम कृषि व औद्योगिक संभावनायों का पूर्णतया उपयोग करने के लिए राज्य सरकार व नाबार्ड को सम्बद्ध सुविधाओं(नर्सरी, सिचाई, सड़क व यातायात, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग व संवेष्ठन हाउस, विपणन इत्यादि) के विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। जब तक इन सम्बद्ध सुविधाओं का विकास नहीं होगा तब तक अपेक्षित उपलब्धि धरातलीय स्तर पर दृष्टिगोचर नहीं होगी। इसके अतिरिक्त राज्य को देश का एग्रो प्रोसेसिंग हब बनाने के लिए कृषि व सहायक क्षेत्रों (फूलबानी, बागवानी, मत्स्यपालन, पशुपालन, दुग्धउत्पादन इत्यादि) को भी विकसित करने की आवश्यकता हैं। यह राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ जन पलायन जैसी प्रमुख व ज्वलन्त समस्या का भी निवारण करने मे सहायक होगा।

4. **विश्लेषण व सुझाव**– खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सुझाव देने से पहले भारत मे इन उद्योगों के लिए उपलब्ध परिस्थितियों का स्वॉट विश्लेषण (स्ट्रेन्थस्, वीकनेसेस्, औपोरच्युनिटी, थ्रेटस्) करना आवश्यक है (सारणी–9)। इसी विश्लेषण के आधार पर समस्याओं का निवारण सम्भव है।

सारिणी–10: खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भारत में उपलब्ध परिस्थितियों का स्वॉट विश्लेषण

स्ट्रेन्थस् (शक्तियां)	वीकनेसेस् (कमजोरियां)
➢ प्राचुर्य प्राकृतिक संसाधनों व विविध जलवायु परिस्थितियों का देश ➢ 1.3 बिलियन जनसख्या के साथ विश्व की सबसे बडी प्रजातान्त्रिक सत्ता ➢ खाद्य सामग्रियों की विविधता व बहुतायत मे प्राप्ति ➢ सरकार द्वारा प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त ➢ प्रगतिशील, सरलीकृत, व विवेकीकृत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर संरचना ➢ वृहद विर्निमाण सुविधायें ➢ वृहद घरेलू बाजार व मांग ➢ वृहद रोजगार सृजन उद्योग ➢ निम्न उत्पादन लागत ➢ सूचना क्रान्ति के फलस्वरूप तकनीकि प्रयोग तक पहुँच ➢ इन्फ्रास्ट्रचर के तीव्र विकास का लाभ	➢ आपूर्ति व्यवस्था में अनियमितता (मौसमी कच्चा माल) ➢ उपयुक्त मूलभूत सुविधाओं का अभाव ➢ कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता ➢ अन्तर्राष्ट्रीय प्रमापों के अनुसार गुणवत्ता नियन्त्रण व परीक्षण विधि का अभाव ➢ मध्यथों की अधिकता के कारण असक्षम आपूर्ति (प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण व वितरण सुविधा की कमी) ➢ आपूर्ति श्रृंखला में व्यवस्थागत अनियमितता (खरीद के लिए एपीएमसी बाजार पर निर्भरता) ➢ शोध, विकास, प्रयोगशाला, व उद्योगों के मध्य अपर्याप्त सामंजस्य (प्रसंस्कृत विविधता की कमी) ➢ सूचना प्रबन्ध मे उपयुक्त स्वचालकता का अभाव ➢ मौसम पर निर्भरता के कारण परिचालन व क्षमता का कम उपयोग

औपोरच्युनिटी(अवसर)	थ्रेटस्(खतरे)
➢ 127+ एग्रो क्लामेटिक जोन ➢ फूड पार्क व एग्रो निर्यात जोन की स्थापना ➢ जीवन शैली मे परिवर्तन व आकांक्षाओं का बढ़ना ➢ प्रयोज्य आय व खाद्य उत्पादों पर खर्च में बढ़ोत्तरी ➢ संगठित खुदरा व निजी क्षेत्रों के प्रवेश में वृद्धि ➢ छोटे परिवारों व कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि ➢ क्रियाशील भोजन/न्यूट्राश्युटिकल्स की मांग ➢ वैश्वीकृत बाजार मे पहुँच	➢ खाद्य उत्पादों की सांस्कृतिक व क्रय योग्य प्राथमिकता ➢ कर का अधिक बोझ ➢ वैश्विक बाजार में गला–काट प्रतिस्पर्द्धा ➢ अन्य उद्योगो व पेशो की तुलना मे प्रशिक्षित मानवीय श्रम का अभाव ➢ प्रसंस्कृत उत्पादो में तीव्र परिवर्तन व विकास के कारण तीव अप्रचलन ➢ अधिक रहतिया वहन लागत

प्रसंस्करण के उच्चतर स्तर सहित एक सुविकसित, सशक्त, व ऊर्जावान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए सुझाव इस प्रकार है–

- भारत में खाद्यान्नों की दशा में फसलोत्तर व फलों की दशा में खेतों मे होने वाली बर्बादी व छीजन को घटाने का प्रयास करना चाहिये[13]
- कृषि उपज का विविधीकरण, व्यवसायीकरण, उपयोगिता संवर्धन, व संचय काल बढ़ाना
- किसानों की वैकल्पिक आय को बढ़ाना, व रोजगारों व खाद्य पदार्थों के निर्यात हेतु बाजार का सृजन
- किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य व उपभोक्ताओं को नियमित उत्पाद पूर्ति सुनिश्चित कराना
- प्रसंस्कृत उत्पादों के संवेष्ठन, ब्रॉन्डिग, गुणवत्ता, व स्वच्छता पर ध्यान देना[14]
- मध्यस्थों पर लगाम लगाकर प्रसंस्कृत उत्पादों के मूल्यों को स्थिर बनाए रखना
- आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रतिष्ठापन व तकनीकी रहित असंगठित प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित करना
- फसलोत्तर मूलभूत सुविधायें(भंडारण, परिवहन, कोल्ड चेन, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आदि) उपलब्ध करवाकर खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला में सभी स्तरों पर अपव्यय को कम करना
- मेगा फूड पार्क, समेकित कोल्ड चेन, व पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण[15]
- उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित प्रभारों व करों के युक्तीकरण को प्रोत्साहित करना
- उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला में अंतरालों को कम करना
- प्रबंधकों, उद्यमियों व कुशल श्रमिकों की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव संसाधन विकास
- विश्लेषण व परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता, खाद्य मानकों के निर्धारण व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उनके सामंजस्य कर निर्यात संवर्द्धन लाभ प्राप्ति
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की तलाश
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता व संभावना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न अध्ययन/सर्वेक्षण, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनेक अधिनियमों, अभिकरणों, व नियामक संस्थाओं के कारण प्रशासन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एकल प्रशासन व्यवस्था को लागू करना
- प्राथमिक क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित कर द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का विस्तार कर मूल्य संवर्द्धन करना

5. **निष्कर्ष**– भारत कृषि उत्पाद व पशुधन के मामले मे विश्व में अग्रणीय है। खाद्य उत्पादों के भारी उत्पादन के बावजूद, खाद्य स्फीति व खाद्य सुरक्षा के मुद्दे देश में नीति निर्माताओं के लिए गहन चिंता का विषय हैं क्योंकि ये भारतीयों की मूलभूत आवश्यकता–पर्याप्त, स्वस्थ व किफायती भोजन को प्रभावित करते हैं।[16] खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति के संवेदनशील मुद्दों को हल करने व लोगों को सम्पूर्ण व पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है। अतः सरकार को इन उद्योगों के स्वस्थ विकास के लिए एक प्रेरक परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। 'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र चिन्हित किया हैं व इन उद्योगों मे विनियोग के अनेक अवसर भी प्रदान किए हैं।[17] 30 जून, 2017 की मध्यरात्रि को लागू किए गए वस्तु व सेवा कर (जी0एस0टी0) मे भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशिष्ट कर छूट प्रदान की गयी है। आधारभूत कच्चे खाद्य उत्पादो (अनाज, मांस, अंडे आदि) को कर से पूर्ण छूट प्रदान की गयी है। अन्य प्रसंस्कृत

उत्पादो पर 12 से 28% की दर से जी0एस0टी0 लगेगा।[18] यह पहल निःसंदेह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित कर राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक, व मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने मे सहायक होगी।

सन्दर्भ

1. पन्त, प्रीति(2015), "भारत में हरित क्रान्ति के पूर्व एवं पश्चात् कृषि उत्पादकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन", अनुसंधान विज्ञान शोध पत्रिका, खण्ड 3, अंक 1, मु0पृ0 11–19।
2. नियोजन आयोग, भारत सरकार(2002), "रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन इण्डिया विजन 2020", पृ0–38।
3. सिह, एस0 पी0; फिस्सेहा एवं ऐकेनक(2008), "द फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री इन इण्डियाः चैलेन्जेस् एण्ड औपोरच्युनिटीज्", जर्नल ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूस्न रिसर्च, खण्ड 43, अंक 1, मु0पृ0 81–89।
4. स्विस बिज्नस हब इण्डिया, "इण्डिया फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री", मु0पृ0 02–13।
5. दादीभवि, आर0 वी0 एवं बागल कोटि, एस0 टी0(1999) "ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज् इन इण्डिया ", योजना, नई दिल्ली, मु0पृ0 13–16।
6. भटनागर, पी0 एस0(2000) "फूड प्रोसेसिंग इन्डसट्रीज–ए सनराइज सेक्टर", मु0पृ0 28–29।
7. सरकार, संदीप एवं करन, के0 अनूप(2005) "ग्रामीण प्रसंस्करण इकाइयों/उद्योगों की अद्यतन स्थिति और संभावनाएं", सामयिक निबन्ध–37, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, नाबार्ड, मु0पृ0 101–109।
8. ए0एस0ए0 एण्ड एसोसिएटस् एल0एल0पी0(ए मेम्बर फर्म ऑफ एन0आई0एस0 ग्लोबल), फरवरी (2015),"ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन फूड प्रोसेसिंग इन इण्डिया"
9. फिक्की(2012)"प्रोसेसड् फूड इन इण्डियाः इनेब्लर्स् एण्ड बैरियर्स्", छठा फूड वर्ल्ड इण्डिया 2012– ग्लोबल कन्वेंशन फॉर फूड, बिजनस एण्ड इन्डसट्रीज।
10. दत्त एवं सुन्दरम्, "इण्डियन इकोनोमी", एस0 चांद पब्लिकेशनस्, मु0पृ0 752–760।
11. राजाराम, के0(1999){संकलित}"इण्डियन इकोनोमी एण्ड जियोग्राफी ऑफ इण्डिया", स्पेक्ट्रम इण्डिया, मु0पृ0 350–364।
12. आर.बी.आई, भारत सरकार (2015) "सांख्यकीय डायरी"।
13. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, "वार्षिक प्रतिवेदन", विभिन्न अंक।
14. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण,"वार्षिक प्रतिवेदन", विभिन्न अंक।
15. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,"वार्षिक प्रतिवेदन", विभिन्न अंक।
16. नाबार्ड, उत्तराखंड,"स्टेट फोकस पेपर", विभिन्न अंक।
17. नाबार्ड, "वार्षिक प्रतिवेदन", विभिन्न अंक।
18. **वेबसाइटः**

- www.ibef.org
- www.makeinindia.com/sector/food-processing